



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 24, 2003/फाल्गुन 5, 1924

No. 181]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 24, 2003/PHALGUNA 5, 1924

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2003

का.आ. 216(अ).—बहु-राष्ट्रीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत केन्द्रीय पंजीकार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शक्तियां राष्ट्रीय/संघ शासित क्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीकार द्वारा अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में स्थित समितियों के संबंध में भी प्रयोग में लाई जा सकेंगी, जोकि निम्नलिखित शर्तों एवं दिशानिर्देशों के विषयाधीन होंगी कि :—

1. राष्ट्रीय सहकारी समिति के संबंध में ऐसी शक्तियां इन अधिकारियों द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जा सकेंगी।
2. अधिकारी (न्यायालय मामलों से इतर) इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (i) के अंतर्गत नियुक्त केन्द्रीय पंजीकार द्वारा समय-समय पर दिए दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
3. सहकारी समितियों के राज्य पंजीकार द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति निम्नलिखित दिशानिर्देशों के विषयाधीन होगी :—
 - (क) संगठनात्मक एवं वैधानिक मामलों से संबंधित विवादों के मामले में मध्यस्थ, प्रैक्टिस करने वाले वकील अथवा न्यायिक/सिविल सेवाओं के सेवानिवृत्त सदस्य अथवा सहकारिता विभाग के कम से कम उप-पंजीकार या अधिक स्तर के ऐसे अधिकारी जो नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष पूर्व से पहले सेवानिवृत्त न हुए हों, होने चाहिए।
 - (ख) वसूली विवादों सहित वित्तीय एवं बैंकिंग मामलों से संबंधित विवादों के मामलों में नियुक्ति के लिए खंड 3 (क) में सूचीबद्ध व्यक्तियों के अतिरिक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स/आई. सी. डब्ल्यू. ए./सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों (सेवानिवृत्ति दो वर्ष से पूर्व की न हो) जैसे वित्तीय एवं लेखा का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों पर विचार किया जा सकता है।
4. अनुमोदित मध्यस्थों की सूची अनुमोदन के 15 दिनों के भीतर केन्द्रीय पंजीकार को प्रस्तुत की जाएगी। सभी अनुमोदित मध्यस्थों की अद्यतन सूची तिमाही आधार पर केन्द्रीय पंजीकार को भेजी जानी चाहिए।

[फा. सं. एल-11012/3/2002-एल एंड एम]

के. एस. भोरिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE**(Department of Agriculture and Co-operation)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th February, 2003

S. O. 216(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 4 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 (39 of 2002), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by the Central Registrar under Section 84 of the Act shall also be exercisable by Registrar of Co-operative Societies of the States/UTs in respect of the societies located in their respective jurisdiction, subject to the following guidelines and conditions, that :—

1. Such powers in relation to a National Co-operative Society shall not be exercisable by these officers.
2. The officers shall comply with the directions (other than court cases) as may be given by the Central Registrar, appointed under Sub-section (1) of Section 4 of this Act, from time to time.
3. Appointment of arbitrators by the State Registrar of co-operative societies shall be subject to following guidelines :—
 - (a) In case of disputes relating to organizational and legal matters, arbitrators should either be a practicing Advocate or retired member of Judicial/Civil services or officers at least of the level of Deputy Registrar and above of co-operative department retired not more than two years prior to the date of appointment.
 - (b) In case of disputes relating to financial and banking matters including recovery disputes, persons having financial and accounting background like Chartered Accountants/ICWAs/retired bank officers (retired not earlier than two years) may also be considered for appointment in addition to the persons listed in clause 3(a).
4. The list of approved arbitrators shall be submitted to the Central Registrar within 15 days of approval. The updated list of all the approved arbitrators should be sent to the Central Registrar on quarterly basis.

[F. No. L-11012/3/2002-L&M]

K. S. BHORIA, Jt. Secy.